



VISION IAS

www.visionias.in



GENERAL STUDIES (TEST CODE : 1836)

Name of Candidate	Vikash Senthya	Registration Number	398329
Medium Eng./Hindi	Hindi	Date	09/09/22
Center	MN		

INDEX TABLE

Q. No.	Maximum Marks	Marks Obtained
1	10	
2	10	
3	10	
4	10	
5	10	
6	10	
7	10	
8	10	
9	10	
10	10	
11	15	
12	15	
13	15	
14	15	
15	15	
16	15	
17	15	
18	15	
19	15	
20	15	

Total Marks Obtained:

Remarks:

INSTRUCTIONS

- Do furnish the appropriate details in the answer sheet (viz. Name, Registration Number and Test Code).
उत्तर पुस्तिका में सूचनाएं भरना आवश्यक है (नाम, प्रश्न-पत्र कोड, विद्यार्थी क्रमांक आदि)।
- There are **TWENTY** questions printed in **ENGLISH & HINDI** इसमें बीस प्रश्न हैं अंग्रेजी और हिन्दी में छपे हैं।
- All questions are compulsory.**
सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।
- The number of marks carried by a question/part is indicated against it.
प्रत्येक प्रश्न/भाग के अंक उसके सामने दिए गए हैं।
- Answers must be written in the medium authorized in the Admission Certificate, which must be stated clearly on the cover of this Question-Cum-Answer (QCA) Booklet in the space provided. No marks will be given for answers written in medium other than the authorized one.
प्रश्नों के उत्तर उसी माध्यम में लिखे जाने चाहिए जिसका उल्लेख आपके प्रवेश पत्र में किया गया है और उस माध्यम का स्पष्ट उल्लेख प्रश्न-सह-उत्तर (क्यूसीए) पुस्तिका के मुख्य पृष्ठ पर अंकित निर्दिष्ट स्थान पर किया जाना चाहिए। उल्लिखित माध्यम के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम में लिए गए उत्तर पर कोई अंक नहीं मिलेंगे।
- Word limit in questions, if specified, should be adhered to.
प्रश्नों में शब्द सीमा, जहाँ विनिर्दिष्ट है, का अनुसरण किया जाना चाहिए।
- Any page or portion of the page left blank in the Question-Cum-Answer Booklet must be clearly struck off.
उत्तर पुस्तिका में खाली छोड़ा हुआ पृष्ठ या उसके अंश को स्पष्ट रूप से काटा जाना चाहिए।

16-B, 2nd Floor, Above National Trust Building, Bada Bazar Marg, Old Rajinder Nagar, Delhi-110060

Plot No. 857, 1st Floor, Banda Bahadur Marg (Opp Punjab & Sindh Bank), Dr. Mukherjee Nagar
Delhi- 110009

EVALUATION INDICATORS

1. Contextual Competence
2. Content Competence
3. Language Competence
4. Introduction Competence
5. Structure - Presentation Competence
6. Conclusion Competence

Overall Macro Comments / feedback / suggestions on Answer Booklet:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

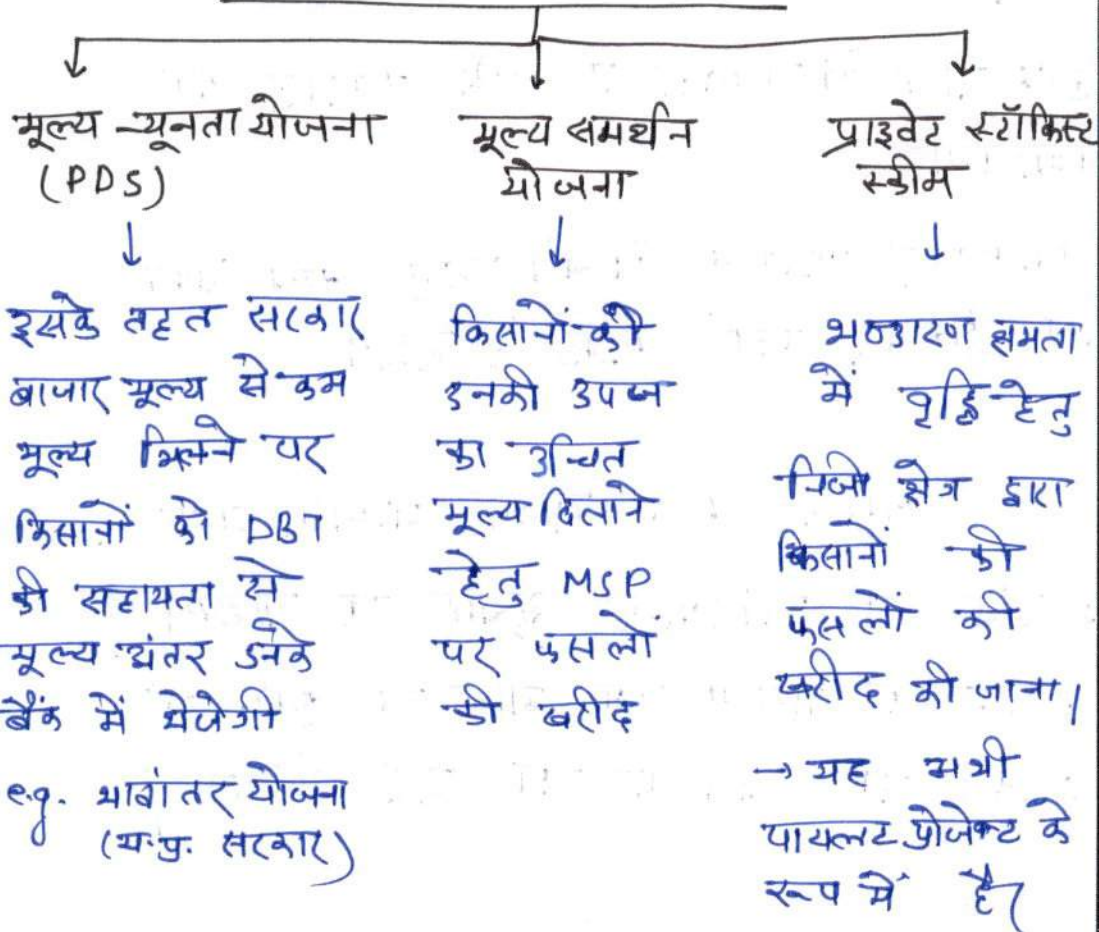
All the Best

1. The PM-AASHA scheme is aimed at improving procurement mechanism as well as ensuring remunerative prices for farmers. In this context, highlight the various components of the scheme and discuss the concerns associated with it. (150 words) 10

पीएम-आशा योजना का उद्देश्य खरीद तंत्र में सुधार के साथ-साथ किसानों के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करना है। इस संदर्भ में, योजना के विभिन्न घटकों को रेखांकित कीजिए तथा इससे जुड़ी चिंताओं पर चर्चा कीजिए।

सरकार ने 2022 तक किसानों की धान दौगुनी खस करने व खरीद तंत्र में सुधार करने के लिए PM-आशा योजना को लॉन्च किया है।

योजना के विभिन्न घटक



PM-भाशा योजना के लाभ

- 1- किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य प्राप्त होगा।
- 2- किसानों की आय दोगुनी करने में सक्षम
- 3- कृषि विपणन व्यवस्था में सुधार
- 4- निजी क्षेत्र के सहयोग से भंडारण की समस्या समाप्त तथा अधिक समावेशी खरीद
- 5- कृषि क्षेत्र में निवेश से कृषि विकास की संभावना
- 6- MSP पर फसल बेचने हेतु लम्बे समय तक इंतजार नहीं PDS के कारण

अतः PM-भाशा योजना कृषि खरीद तंत्र में संस्थागत सुधार के माध्यम से 2022 तक दोगुनी कृषक आय व कृषि में वृद्धि गारंटी की समस्या को हल करेगी।

2. Explaining the concept of blended finance, discuss the role it can play in mobilizing capital for infrastructure development in developing countries like India.

(150 words) 10

मिश्रित वित्त की अवधारणा की व्याख्या करते हुए, भारत जैसे विकासशील देशों में अवसंरचना विकास हेतु पूंजी जुटाने में इसकी भूमिका पर चर्चा कीजिए।

मिश्रित वित्त से तात्पर्य देश के विकास में सरकारी व निजी क्षेत्र के धन का प्रयोग करने से है।

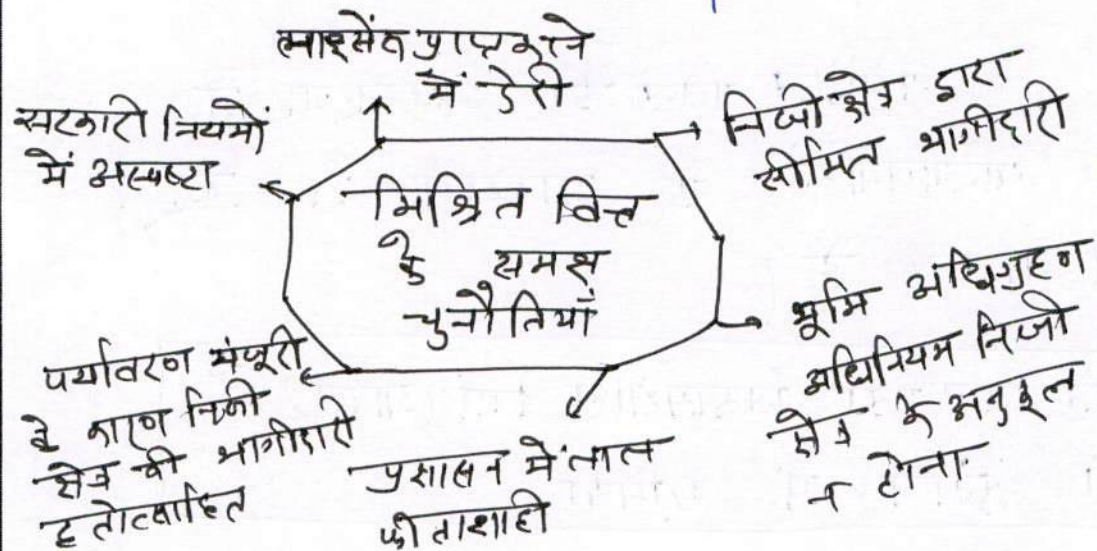
$$\text{मिश्रित वित्त} = \frac{\text{सरकारी वित्त}}{\text{वित्त}} + \frac{\text{निजी क्षेत्र से प्राप्त वित्त}}{\text{वित्त}}$$

मिश्रित वित्त की अवधारणा को PPP परियोजनाओं के माध्यम से लागू किया जाता है।

मिश्रित वित्त की विकासशील देशों (भारत) में पूर्ण क्षमता में भूमिका

→ भारत में 2030 तक अर्थव्यवस्था को 7-8% की गति से बढ़ा देने हेतु अवसंरचना पर \$4.5 लाख करोड़ की आवश्यकता है जिसे निजी वित्त के सहयोग से पूरा किया जा सकता है।

- 2- निजी क्षेत्र नवीन तकनीक व नवाचारों से वित्त की कार्यक्षमता में वृद्धि कर रहे हैं।
- 3- निजी क्षेत्र की कृषि वित्तीय प्रबंधन व्यवस्था, कार्य पूर्ण करने में तेजी आदि के कारण वित्त का उचित उपयोग।
- 4- सरकार ने मिश्रित वित्त की अवधारणा के लिए NIP, NMP, विनिवेश आदि को संचालित किया है।



अतः सरकार को एक बुद्धि व समन्वयात्मक नीति लागू करनी चाहिए ताकि मिश्रित वित्त के माध्यम से अवसंरचना विकास द्वारा भारत की लॉजिस्टिक्स लागत कम हो सके।

3. Discuss the challenges faced in the revival and revamp of dry ports in India and state the measures that can be adopted in this regard.

(150 words) 10

भारत में शुष्क पत्तनों (ड्राई पोर्ट्स) के पुनरुद्धार और सुधार में आने वाली चुनौतियों पर चर्चा कीजिए तथा इस संबंध में अपनाए जाने वाले उपायों का सुझाव दीजिए।

शुष्क पत्तनों से आशय
समुद्र तट से दूर बनाए गए पत्तनों
से होता है।

चुनौतियाँ

- निजी क्षेत्र की सीमित भागीदारी
- वित्त की समस्या
- आवश्यक कौशल का अभाव
- व्यवसायिक व वित्तीय संबंधन की
असमता

सुझाव - सरकार द्वारा अधिकनियमित मीटर
घोटी अधिनियम का पुरानी डिपॉजिट

- PPP परियोजनाओं को एक प्रकार डिजाइन
करना कि निजी क्षेत्र आकर्षित
- तकनीकी कर्मचारियों का कलाता लेना।

4. Monoculture is one of the major threats to ensuring food security and sustainability of Indian agriculture. Discuss. (150 words) 10

एकल कृषि (मोनोकल्चर) खाद्य सुरक्षा और भारतीय कृषि की संधारणीयता सुनिश्चित करने के समक्ष विद्यमान प्रमुख खतरों में से एक है। चर्चा कीजिए।

एकल कृषि से तात्पर्य किसी भूमि में एक ही प्रकार के फसलों को उगाने से है। यह फसल विविधीकरण से विपरीत है।

जैसे - हरित क्रांति से जहाँ में केवल गेहूँ या चावल की फसल उगाना।

एकल कृषि - खाद्य सुरक्षा के लिए खतरा

- 1- खाद्य सुरक्षा में पोषण युक्त विविध आहार आवश्यक, जबकि एकल कृषि से एक ही प्रकार के उत्पाद प्राप्त जिससे हिउन हंगर की समस्या
- 2- एकल कृषि से निरंतर प्रयोग से उत्पादन में कमी

एकल कृषि, कृषि की संधारणीयता को भी प्रभावित करती है -

- 1- एकल कृषि से मृदा में आवश्यक

पोषक तत्वों की कमी हो जाती है जिससे मृदा की उर्वरता में कमी आती है - लगातार जैडू या नाबल के प्रयोग से N_2 की कमी

2- इसके लिए अधिक मात्रा में उर्वरक व कीटनाशकों का प्रयोग जो पल, वायु व मृदा प्रदूषण का कारण

3- फसलों में रोगों से बढ़ने की संभावना में वृद्धि

सतत कृषि के लिए

- फसल विविधीकरण
- जैविक कृषि व ZBNF
- सूक्ष्म सिंचाई पद्धतियाँ
- कम जल गहरा फसले
- जलवायवीय इशामों के अनुकूल कृषि

अतः सरकार द्वारा MSP व्यवस्था, उर्वरक सब्सिडी व अन्य नीतिगत उपायों के तार्किकीकरण द्वारा फसल विविधीकरण को प्रोत्साहित करना चाहिए ।

5. While highlighting the impact of single-use plastic on health and the environment, state the recent efforts taken by the government to curb plastic pollution in India. (150 words) 10

स्वास्थ्य और पर्यावरण पर एकल-उपयोग वाले प्लास्टिक के प्रभाव को रेखांकित करते हुए, भारत में प्लास्टिक प्रदूषण को रोकने के लिए सरकार द्वारा हाल ही में किए गए प्रयासों का उल्लेख कीजिए।

प्लास्टिक एक नॉन-डिग्रेडेबल
मपशिष्ट है जो लम्बे समय तक
पर्यावरण को प्रदूषित करता है।

स्वास्थ्य व पर्यावरण पर सिंगल यूज प्लास्टिक के प्रभाव

- 1 - सिंगल यूज प्लास्टिक का सामान्यतः पुनः चकण के उपयोग नहीं किया जा सकता, अतः ये अधिक खतरनाक
- 2 - प्लास्टिक लम्बे समय तक मृदा में रहकर मृदा प्रदूषण व मृदा को प्रदूषित करने से सीमित करते हैं।
- 3 - जल प्रदूषण - भूमिगत जल रिसाव द्वारा जल प्रदूषण जल निकायों में प्लास्टिक मपशिष्ट डेके जाने से
- 4 - वायु प्रदूषण - प्लास्टिक से जलाने पर

CO₂, CO जैसी विषैली गैसों का
उत्सर्जन

समुद्री प्रदूषण के लिए प्लास्टिक प्रमुख कारक

6. स्वास्थ्य पर [जल, वायु, मृदा प्रदूषण का
स्वास्थ्य पर प्रभाव
समुद्री जीवों में जैवसंचयन
व जैव आवर्धन के द्वारा सम्पूर्ण
खाद्य श्रृंखला प्रवेश

सरकार द्वारा
सिंगल यूज
प्लास्टिक को
रोकने के उपाय

- प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन
अनियम 2020 के तहत
सिंगल यूज प्लास्टिक पर रोक
- 50 माइक्रोन मोटाई से अधिक
प्लास्टिक बैग का प्रयोग
- EPR के द्वारा उत्पादकों को
अपशिष्ट निपटान हेतु जिम्मेदार
बनाना
- सोशल मीडिया के माध्यम से
'प्लास्टिक बैन' कैंपेन चलाना

सतत विकास की प्राप्ति के लिए
सरकार को जनजागरूकता का कठोर नियमों
के साथ वैश्विक समन्वय द्वारा प्लास्टिक
को कम करने का प्रयास करना चाहिए।

6. Aapda Mitra – a force of volunteers from across India trained in disaster response – is becoming a game changer in the field of disaster management in the country. Elaborate. (150 words) 10

आपदा मित्र-आपदा प्रतिक्रिया हेतु प्रशिक्षित भारत भर के स्वयंसेवकों का एक बल-देश में आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में एक गेम चेंजर के रूप में उभर रहा है। सविस्तार वर्णन कीजिए।

आपदा एक ऐसी अप्रत्याशित
संघट्ट की स्थिति होती है जो बड़े
समय पर जन व जन की हानि
का कारण बनती है।

अतः आपदा के प्रभाव व
तीव्रता को कम करने के लिए आपदा
प्रबंधन रणनीति के रूप में सरकार
आपदा मित्र (प्रशिक्षित स्वयंसेवक) को बढ़ावा
दे रही है।

आपदा मित्र - आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में गेम चेंजर

1. सर्वप्रथम आपदा के प्रति उत्तिष्ठिया जनसमुदाय
द्वारा → ऐसे में आपदा मित्र जन-
समुदाय को प्रशिक्षित कर, क्षरित आपदा
प्रतिक्रिया।

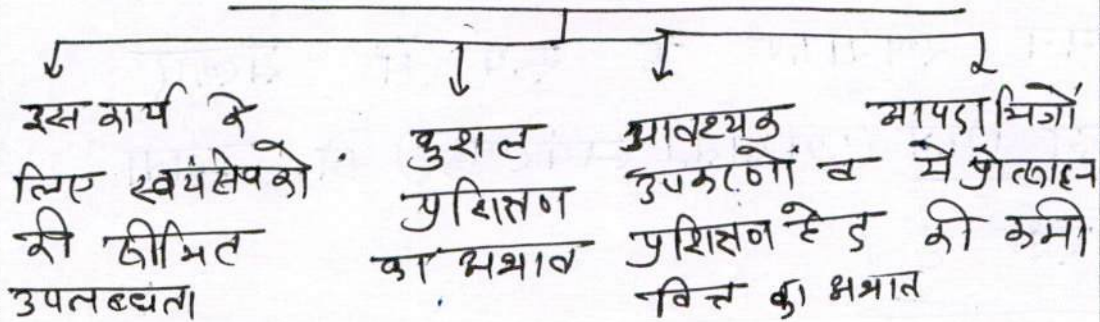
2- आपदा मित्रों द्वारा आपदा के समय
राहत व बचाव कार्य का कुशलता

से सम्पन्न करना ।

3- समय-समय पर मॉक ड्रिल, उद्देश्य
आदि के द्वारा जनसमुदाय को आपदाओं
के लिए तैयार करना ।

4- मिटिगेशन व तैयारी के दौरान आपदा
मित्रों द्वारा जनसमुदाय के सहयोग से
नवीन तकनीकों का प्रसार

आपदा मित्रों के समस्त समस्याएँ



अतः सरकार को एक कुशल
संस्थागत तंत्र व विनियामक नीति के माध्यम
से आपदा मित्रों को बढ़ावा देना चाहिए
जिससे आपदा पर व्यय होने लाखों
डॉलरों को बचाया जा सकता है ।

7. Why is the rise in lone wolf attacks considered as a serious challenge for security agencies around the world? Highlight the role of the internet in exacerbating such attacks. (150 words) 10

विश्व भर में लोन वुल्फ हमलों में वृद्धि को सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक गंभीर चुनौती क्यों माना जाता है? ऐसे हमलों की वृद्धि में इंटरनेट की भूमिका पर प्रकाश डालिए।

लोन वुल्फ अटैक एकल व्यक्ति द्वारा हिंसक व अवैध गतिविधि को अंजाम दिए जाने से संबंधित है जिससे व्यापक हानि होती है।

ऐसे व्यक्ति किसी संगठन, विचारधारा आदि से जुड़े भी हो सकते हैं और स्वतंत्र रूप से कार्य भी कर सकते हैं।

लोन वुल्फ हमलों में यह कारण

- 1- इन्हें अंजाम देना अधिक आसान होता है।
- 2- USA जैसे देशों में बन्दूक लाइसेंस की सरल उपलब्धता
- 3- सुरक्षा एजेंसियों की सीमित जरूरत
- 4- बढ़ते शहरीकरण के कारण अवसाद में रहने
5. इंटरनेट की भूमिका - इस बड़े व्यक्तियों से निरंतर सम्पर्क में रहना
→ अत्याचारों को डेकर हमले के लिए खुद को तैयार करना

- हमले के स्थान की पहले से पूर्ण जानकारी प्राप्त करने में ससम
→ इंटरनेट के माध्यम से फेक-न्यूज व कटरवादी विचारों का बढ़ना

सुरक्षा रणनीतियों के लिए जंजीर-पुनौती

- 1- ऐसे व्यक्तियों को पहचानना मुश्किल तथा आसूचना-तंत्र के चरे से बाहर
- 2- जनता के बीच में रहकर ही कार्य करते हैं।
- 3- इनकी योजनाओं को खिफ़ी चही जानते हैं, मतलब उनका पता लगाना कठिन
- 4 - हमले के लिए अत्याधुनिक तकनीकों का प्रयोग

लोन वुल्व हमले को रोकने हेतु वैरिक्स समुदाय को एक साथ आना चाहिए और प्रभावी सुरक्षा व्यवस्था के साथ युवाओं को कटरवादी बनने से रोकने के प्रयास करने चाहिए।

8. The fundamental inefficiencies embedded in our military structures and processes are now being addressed through a slew of defence reforms in the country. Discuss. (150 words) 10

हमारे सैन्य ढांचे और प्रक्रियाओं में अंतर्निहित मूलभूत अक्षमताओं को अब देश में विभिन्न रक्षा सुधारों के माध्यम से दूर किया जा रहा है। चर्चा कीजिए।

भारत में विस्तरीय सैन्य
ढांचा पाया जाता है -

- थल सेना
 - जल सेना
 - वायु सेना
- रक्षा मंत्रालय

इसके अतिरिक्त CAPF के तहत चेरा-
मिलिटी फोर्स के तहत ITBP, BSF,
SSB आदि पाए जाते हैं।

सैन्य ढांचे में और उद्दिष्टों में समस्याएँ

- ① विभिन्न सेनाओं में समन्वय का अभाव
- ② आधुनिक सैन्य उपकरणों की कमी
- ③ सैन्य उपकरणों की खरीद में भ्रष्टाचार तथा विलंब
- ④ सेनाओं की बिना प्रशिक्षण के अन्य विषयों पर नियोजित करना जैसे - ITBP को नक्सलियों के विरुद्ध

सरकार द्वारा किए जा रहे विभिन्न सैन्य पुर्नधार

- 1- चीफ़ ऑफ़ डिफेंस स्टाफ़ की स्थापना
↳ विभिन्न सैनयों के लिए पुनर्गठन
नीति निमन्त्रि
- 2- इंटीग्रेटेड थियेटर रमान का निर्माण
↳ सैनयों में समन्वय व कुशलता में
वृद्धि
- 3- DPP-2020 खरीद उद्दिष्टा तीव्र व
पारदर्शी
- 4- Integrated Battle Group (IBG) का
निमन्त्रि
- 5- सैन्यकर समिति के अनुरूप एक बीमा एक
सैन्य के सिद्धान्त व लकार विमर्शक
रही है।

एक कुशल व पुनर्गठन सैन्य
समता भारत की आंतरिक सुरक्षा पुनर्गठनों
से निपटने के साथ IOR में Net
security Provider की भूमिका निभाने में मदद
करेगा।

9. In light of the recent establishment of the WHO Global Centre for Traditional Medicine in India, discuss the advantages and challenges in mainstreaming traditional medicine in the country. (150 words) 10

हाल ही में, भारत में डब्ल्यू. एच. ओ. ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की स्थापना के आलोक में, देश में पारंपरिक चिकित्सा को मुख्यधारा में लाने के लाभों और चुनौतियों पर चर्चा कीजिए।

पारंपरिक चिकित्सा लम्बे समय से जनसमुदाय द्वारा उपयोग की जा रही चिकित्सा पद्धतियों के लिए दायित्व नाम है।

जैसे - योग, आयुर्वेद, सोम्बा रिग्वा आदि

सरकार पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली को बढ़ाने पर चला रही है। इसके लिए भारत सरकार ने आयुषमंजालय की स्थापना की जो अभी हाल ही में WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की स्थापना की गई।

पारंपरिक चिकित्सा के लाभ

- 1- इसके साइड इफेक्ट कम होते हैं।
- 2- जनसामान्य में इनकी अत्यधिक पहुँच व विश्वसनीयता

3- आधुनिक निमित्ता पुणालियों की इलना में सस्ते ।

4- क्रीनिक बीमारियों जैसे कैंसर यदि मे इसके लाभ देखे गए हैं ।

5- सम्पूर्ण शरीर का इलाज करते हैं जिसे अधिक प्रभावी

इनको मुख्यधारा में लाने में चुनौतियाँ

- 1- सरकार व स्वास्थ्य कर्मियों के पास इनसे जुड़ी पद्धतियों, परिणामों व बाँकों की सीमित उपलब्धता
- 2- रोग दीक होने में लंबा समय
- 3- कुशल स्वास्थ्य कर्मियों का अभाव
- 4- जनसामान्य द्वारा इनकी उर्पेशा जैसे 2019 में केवल 4% रोगियों ने OPD के स्थान इसका विकल्प चुना

पांथरिक स्वास्थ्य पुणालियों भारत के स्वास्थ्य ढाँचे में कमी का शक साबित होंगे अतः सरकार को इन्हे मुख्यधारा में लाने का प्रयास करना चाहिए ताकि SDG-3 की प्राप्ति हो सके ।

10. Nano Urea Liquid has the potential to transform farming in India and across the world by improving productivity while reducing environmental pollution and input cost. Discuss. (150 words) 10

नैनो यूरिया लिक्विड में पर्यावरण प्रदूषण और इनपुट लागत को कम करने के साथ-साथ उत्पादकता में सुधार करके भारत और विश्व भर में कृषि कार्य को रूपांतरित करने की क्षमता है। चर्चा कीजिए।

नैनो यूरिया लिक्विड यूरिया उर्वरक का एक प्रकार है जिसमें नैनो यूरिया कणों का उपयोग किया जाता है।

भारत में यूरिया उर्वरक का अत्यधिक उपयोग किया जाता है [आदर्श NPK 4:2:1 के स्थान पर 7:2:1] अतः नैनो यूरिया लिक्विड इसका समाधान करने में मदद करेगा।

नैनो यूरिया लिक्विड (NUL) के लाभ-

1- पर्यावरण - अत्यधिक उर्वरक के उपयोग से होने वाले मृदा प्रदूषण व जल प्रदूषण में कमी

2- इनपुट लागत - यूरिया के अधिक उपयोग के लागत अधिक
NUL की बतियों पर दिखाव जिससे सीमित उपयोग तथा लागत में कमी

3- उत्पादकता पर - पत्तियों द्वारा NUL पर
दिड़काव द्वारा पुराल उपयोग

↳ मृदा में अत्यधिक सूरिया से
होने वाली उर्वरता कमी का समाधान
↓
इसका प्रभाव उत्पादकता में वृद्धि

4 - सरकार के वित्तीय बोझ को कम - उर्वरक
क्षमिता में कमी के कारण

5 - NPK उर्वरकों का उचित अनुपात में
प्रयोग

6 - सूरिया की विधि में सीनेज को बचाव

7 - स्वास्थ्य संबंधी प्रभावों में कमी

इस प्रकार NUL इनपुट लागत
में कमी, मृदा की उर्वरता में वृद्धि तथा
भू-जल व मृदा उपकरण में कमी के
माध्यम से विश्व व भारत में कृषि
को सतत वृद्धि की ओर अग्रसर
रेगा।

11. Discuss the domino effect of high crude oil prices on the Indian economy. Also, enumerate the measures that India can take in this context.

(250 words) 15

भारतीय अर्थव्यवस्था पर कच्चे तेल की ऊँची कीमतों के डोमिनो प्रभाव की विवेचना कीजिए। साथ ही, भारत द्वारा इस संदर्भ में अपनाए जा सकने वाले उपायों को सूचीबद्ध कीजिए।

भारत अपने कच्चे तेल की आवश्यकता पूर्ति का 80-85% आयात करता है। अतः तेल की अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों में वृद्धि से घरेलू अर्थव्यवस्था पर अनेक प्रभाव पड़ते हैं।

कच्चे तेल की ऊँची कीमतों का डोमिनो प्रभाव

1- कच्चे तेल की कीमत में वृद्धि

↓
आयात बिल में वृद्धि ⇒ कॉरेक्स में कमी

↓
रुपये का अवमूल्यन

2- घरेलू अर्थव्यवस्था में ईंधन की कीमतों में वृद्धि ⇒ परिवहन लागत अधिक

↓
उत्पादों की लागत अधिक

↓
मुद्रास्फीति

3- मुद्रास्फीति के कारण भारत का

नियति अप्रतिस्पर्धी हो जाता है।
तेल कीमतों में वृद्धि बरेल अर्थव्यवस्था को बाह्य सखों के प्रति सुश्रद्धा बनाती है।

भारत द्वारा इस संदर्भ में अपनाए जा सकने वाले उपाय

1. कच्चे तेल के आयात के स्रोतों का विविधीकरण करना चाहिए
[वर्तमान में 70% आयात पश्चिम एशिया से]
2. घरेलू इंधन के स्रोतों का विकास करना
जैसे - डिजेल, मसम, कावेरी - जोगप्रदी वेस्तिन, कच्चा कारण
3. स्वीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर निर्भरता बढ़ाना, इसके लिए 2022 तक 175 GW व 2030 तक 450 GW के लक्ष्य की प्राप्ति में तेजता लाना।

4- FAME योजना के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों के अंगीकरण को तीव्र करना और इसके लिए कर प्रोत्साहन तथा पर्याप्त चार्जिंग अवसर का विकास करना।

5- पेट्रोल-डीजल में सुपेनॉल मिश्रण द्वारा तेल के आयात में कमी करना।

6- सुपेनॉल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना

1- प्लेस्ट टू इनर्जी जैसे वैकल्पिक को बढ़ावा

अतः अलगाय परिवर्तन के बल

को देखते हुए भारत को तेल आयात अर्थव्यवस्था के स्थान पर सतत ईंधन आपूर्ति पर आधारित व्यवस्था अपनानी चाहिए।

12. The consistent high operating ratio of the Indian Railways is indicative of its incapability to generate high operational surplus. Explain the reasons behind this trend. Also, highlight the remedial measures taken by the government in this regard. (250 words) 15

भारतीय रेलवे का लगातार उच्च परिचालन अनुपात उच्च परिचालन अधिशेष सृजित करने में असमर्थता का संकेत है। इस प्रवृत्ति हेतु उत्तरदायी कारणों को स्पष्ट कीजिए। साथ ही, इस संबंध में सरकार द्वारा किए गए उपचारात्मक उपायों को रेखांकित कीजिए।

यात्री परिवहन की दृष्टि से भारतीय रेल का विश्व में प्रथम स्थान है। वार्षिक प्रतिदिन २५ करोड़ से अधिक यात्री आवागमन करते हैं।

भारतीय रेलवे में लम्बे समय से उच्च परिचालन अनुपात (लगभग 98%) की समस्या देखी गई है जिससे यह उच्च परिचालन अधिशेष उत्पन्न नहीं कर पाता है।

उच्च परिचालन अनुपात के लिए कारण

- 1- रेलों की धरियों व अन्य अवसंरचना का अत्याधुनिक न होना।
- 2- एक ही ट्रेन पर मालगाड़ी तथा यात्री गाड़ी चलाने से विलंब की

समाप्ता ।

- 3 - रेलवे परिसंपत्तियों का अनुचित रखरखाव जिससे उनमें चोरी या नष्ट होने की समस्या ।
- 4 - रेलों में होने वाली दुर्घटनाओं की परिचासन लागत को बढ़ा देती है ।
- 5 - अनुसूचित कर्मचारी व वित्तीय संबंधन
- 6 - प्रतिस्पर्धा के अभाव के कारण निम्न गुणवत्ता
- 7 - सरकारी खरीद (रेलवे हेतु) अव्ययित महंगी व भ्रष्टाचार की समस्या

इस उच्च परिचालन अनुपात के कारण भारतीय रेलवे में कॉल सब्सिडी व्यवस्था बली पड़ती है जिससे भालभाड़ा अंतर्गत हो जाती है । फलस्वरूप माल परिवहन में रेलवे की हिस्सेदारी यह रही है [2020 - सड़क परिवहन - 76% हिस्सेदारी रेलवे - 11 %]

सरकार द्वारा किए गए प्रयास

1- सीमित मात्रा में निजी क्षेत्र की अनुमति
प्रदान की → प्रतिस्पर्धा बढ़ने से
गुणवत्ता में इढ़ि

ए.ग. तेजस, बंदे भारत रेलप्रिय

2 - अहमदाबाद से मुम्बई से लिए जापान
के सहयोग से 'बुलैर ड्रेन परियोजना'
प्रारंभ की है।

3 - अवसंरचना के आधुनिकीकरण का प्रयास

4- तकनीकी के प्रयोग से रेल दुर्घटनाओं
में कमी

जैसे - मानव रहित रेलवे कार

क दुर्घटना व तीव्र रेलवे परिवहन
भारत की लॉजिस्टिक्स कोस्ट (वर्तमान में
14%) को कम कर व्यापार दुरुमता
में इढ़ि होगा।

13. Micro food processing sector is the key driver of growth in the Indian economy as it encourages food processing innovation. In this context, state the challenges faced by the micro food processing sector and discuss how the recent initiatives taken by the government aim to address them.

(250 words) 15

सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्रक भारतीय अर्थव्यवस्था में संवृद्धि का प्रमुख चालक है क्योंकि यह खाद्य प्रसंस्करण नवाचार को प्रोत्साहित करता है। इस संदर्भ में, सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्रक द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियों का उल्लेख कीजिए और चर्चा कीजिए कि किस प्रकार सरकार द्वारा हाल ही में प्रारंभ की गई पहलों का उद्देश्य इनका समाधान करना है।

खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्रक कृषि व
उद्योग के मध्य से गुज़ी होता है।
यह कृषि से प्राप्त अच्छे मात की
प्रसंस्कृत कर उनकी शैल्फ लाइफ बढ़ाता है।

वर्तमान में भारत में अधिकतर
FPI, सूक्ष्म स्तर के हैं।

सूक्ष्म FPI की भूमिका

- किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य
- खाद्य प्रसंस्कृत पदार्थों के निर्यात द्वारा
विदेशी मुद्रा की प्राप्ति
[FPI का कुल निर्यात में 14% हिस्सेदारी]
- ग्रामीण व शहरी स्तर पर लोगों को
अल्पमूल्य रोजगार के अवसर, विशेषतः
महिलाएं व वंचित वर्ग

→ FPI, उद्योगों में नवीन तकनीकों के
उपयोग से निर्यात को बढ़ावा देते हैं।

MFI के समक्ष चुनौतियाँ

- 1- परिचालन के लिए आवश्यक विनियम की कमी
↳ संस्थागत ऋणों तक सीमित पहुँच
- 2- आवश्यक औद्योगिक जन-शक्ति का अभाव
- 3- कमजोर बैंकवर्ड व फोर्ड लिंकेज
↳ कोलु टिरोस जैसी अवसरचना
का अभाव
- 4- सूक्ष्म स्तर पर संचालित होने के
कारण Economy of scale का लाभ
नहीं।
- 5- बड़े उद्योगों से प्रतिस्पर्धा।
- 6- गुणवत्ता युक्त कृषि उत्पादों का
उत्पन्न न होना
- 7- निम्नस्तरीय व प्राथमिक तकनीक का
अभाव

सरकार द्वारा प्रारंभ की पहलें

1- सूक्ष्म MPC का औपचारिकरण योजना
↳ वित्त तक पहुँच में वृद्धि

2- PM - सम्पदा योजना

↓
इसके तहत 6 - उप योजनाएँ

जैसे - बैंकवर्ड, फोरवर्ड लिम्बेज का विकास
- कुशल पेशेवरों के विकास हेतु
प्रशिक्षण आदि ।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग कृषि में
सुधार, किसान आय में वृद्धि तथा
कृषि प्रियति में बढ़ावा देकर
कृषि प्रियति नीति के लक्ष्यों को प्राप्त
करने में सहायक होंगे ।

14. Despite efforts by successive governments, equitable growth remains elusive and income inequality continues to persist in India. Discuss.

(250 words) 15

क्रमिक सरकारों के प्रयासों के बावजूद, न्यायसंगत विकास दुष्प्राप्य बना हुआ है और भारत में आय असमानता निरंतर बनी हुई है। चर्चा कीजिए।

न्यायसंगत विकास से तात्पर्य है कि सभी व्यक्तियों को अपने विकास के लिए आवश्यक संसाधन उचित मात्रा में प्राप्त हो सकें।

सरकारों के उपास - न्यायसंगत विकास की जा पहचानें

1- खाद्य सुरक्षा हेतु

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम

→ जन वितरण प्रणाली

→ मध्यम-श्रेणी भोजन व्यवस्था (PM - पोषण योजना)

→ one nation one ration card

2- गरीबी निवारण हेतु → मनरेगा

→ किसानों को उर्वरक, बिजली, पिनचार्ज आदि में सब्सिडी

→ PM किसान सम्मान निधि के तहत राशि (60000 ₹)

→ श्रमवला योजना के तहत सब्सिडीयुक्त फिलेड आदि

3 - शिक्षा प्राप्ति हेतु - राष्ट्रीय सर्व शिक्षा अभियान
 ↳ राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान
 ↳ स्कूलों में फ्री रैक्लेट, साइडिल, स्मार्टबोर्ड आदि का वितरण

4 - स्वास्थ्य सुविधाओं हेतु - आयुष्मान भारत योजना
 ↳ जननी सुरक्षा योजना
 ↳ मातृ बंधन योजना
 ↳ राष्ट्रीय बृद्धजन स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम

आय वंगत विकास प्राप्त करने में समस्या

- 1- योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन नहीं
- 2- स्वास्थ्यिक लाभार्थियों का लाभ न मिलना
जैसे - राधिका कृषि - PDS में 1.5 करोड़ पन्नी राशन कार्ड
- 3- भ्रष्टाचार के कारण लीकेज की समस्या
जैसे - शोलाकुमार कृषि - PDS में 40% तक लीकेज की समस्या

- 4 - अपने अधिकारों को लेकर जागरूकता का अभाव
 'ज' मनोरंजन में देशवासियों द्वारा रोषण करना
- 5 - योजनाओं का लाभ प्राप्त करने की उद्दिष्ट अधिक जटिल
- अतः अक्सर में 40% से अधिक धनता के राशिकर्मी माचार से लिंक नहीं

इस सब कारणों के कारण भारत में आय असमानता बढ़ी है।
ऑक्सडेन रिपोर्ट के अनुसार -

टॉप 1% आयी - 57% कंपनी
 टॉप 10% आयी - 77% कंपनी
 बॉटम 50% आयी - 6% कंपनी

अतः समावेशी विकास के माध्यम से आय असमानता को बर करना चाहिए तथा वार्षिक अर्थी में सर्वोच्च मारती के अनुसार सामाजिक कल्याण की प्राप्ति होगी ।

15. Stating the factors that determine the employment situation of an economy in the long-term, discuss the measures that are needed for India to address its unemployment problem. (250 words) 15

किसी अर्थव्यवस्था की दीर्घावधि में रोजगार की स्थिति को निर्धारित करने वाले कारकों का उल्लेख करते हुए, उन उपायों की विवेचना कीजिए जो भारत में बेरोजगारी की समस्या के समाधान हेतु आवश्यक हैं।

रोजगार की स्थिति को अनेक
कारक प्रभावित करते हैं जैसे —

- 1- अर्थव्यवस्था में उच्च वृद्धि दर होनी चाहिए ।
- 2- अर्थव्यवस्था में औद्योगिक आधार विस्तृत तथा सुदृढ़ होना चाहिए ।
- 3- कृषि क्षेत्र पर निर्यात-आश्रितता का अनुपात कम होना चाहिए ताकि उच्च-बेरोजगारी की समस्या न हो।
- 4- निवेश अनुकूल माहौल जिससे FDI आकर्षित हो ।
- 5- उद्योगों पर सरकार का सीमित नियंत्रण तथा उद्योगों के लिए रीज ऑफ इंडग बिजनेस

ई- बनसंख्या के बस बौशल की उपलब्धता होनी चाहिए।

८- वैश्व बाजार तथा निर्यात में पर्याप्त हिस्सेदारी होनी चाहिए।

भारत में बेरोजगारी

जून २०२२ में भारत में बेरोजगारी दर ७.६% थी। भारत में LFPR अत्यधिक कम लगभग ४०% है तथा महिलाओं में यह और भी कम १% है।

बेरोजगारी की समस्या के समाधान हेतु उपाय

१- भारत के औद्योगिक आधार को मजबूत करने पर बल

[पिछले तीन दशकों से उद्योगों की GDP में भागीदारी १८-१५% पर स्थिर है]

२- युवाओं की पर्याप्त बौशल व उद्योगों की मांग के अनुरूप बौशल प्रदान करना। इसके लिए PM

डिजिटल विकास योजना, उस्ताद योजना भाडि
का उक्ति डिमान-वयन

- 3 - कृषि के विकास द्वारा कृषि में उच्च-न
बेरोजगारी को इर करने का उपाय
- 4 - उद्योग - अकादमिक जगत को मजबूत
बनाना
- 5 - भ्रम-गहन उपयोगों जैसे चमड़ा, वस्त्र
उद्योग भाडि में अधिक निवेश
- 6 - उभावी व पमपि अवसर-चाना विकास करना
- 7 - भ्रमबल का सौच्यारीकरण करना
- 8 - भ्रमकानूनों का उभावी डिमान-वयन

बेरोजगारी की समस्या का
समाधान कर आर्थिक उगाति के माध्यम
से \$5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था के लक्ष्य
को इरा किया जा सकेगा 1

16. In view of the rapidly increasing socio-economic damage caused by disasters, integrating Disaster Risk Reduction (DRR) into development planning requires an effective stakeholder engagement mechanism. Discuss. (250 words) 15

आपदाओं के कारण तेजी से बढ़ रही सामाजिक-आर्थिक क्षति को देखते हुए, आपदा जोखिम न्यूनीकरण (DRR) को विकास योजनाओं में एकीकृत करने के लिए एक प्रभावी हितधारक जुड़ाव तंत्र की आवश्यकता है। विवेचना कीजिए।

आपदा एक भयानक घटना होती है जो बड़े पैमाने पर विनाश उत्पन्न करती है।

उदाहरण - UK में 2013 में ब्रिक्स-घटने से उत्पन्न आपदा
- डेरल की बाढ़ आदि

आपदा के कारण होने वाली आर्थिक क्षति

- 1 - सड़क, रेल, पुल आदि संरचनाएँ नष्ट
- 2 - हजारों व्यक्तियों की जान चली जाती है तथा लाखों व्यक्ति बेघर हो जाते हैं।
- 3 - पर्यावरणीय क्षति
 - जल प्रदूषण
 - हवा का प्रदूषण
 - मृदा क्षति
 - वन विनाश
 - मृदा की गुणवत्ता में गिरावट

वर्तमान में जलवायु परिवर्तन के कारण आपदाओं की आवृत्ति व तीव्रता में वृद्धि देखी गई है।

आपदा जोखिम-सूचीकरण (DDR)

DDR इस अवधारणा पर आधारित है कि आपदाओं को रोका नहीं जा सकता है लेकिन उनके प्रभावों को कम किया जा सकता है इसके लिए आवश्यक है —

- 1- आपदा से पूर्व हितधारकों के साथ पुष्टकर आपदा संभावित क्षेत्रों को मैपिंग करना
- 2- आपदा प्रभावित क्षेत्रों में रिस्क भाकलन के माध्यम से हजार्ड जोनेशन मैप बनाना।
- 3- जनसमुदाय, राज्य सरकार तथा केन्द्र सरकार के माध्यम से

आपदा शमन के उपाय करना ।

4- आपदा रूक तैयारियों को मजबूत बनाना
जैसे - मॉक ड्रिल

- आपदा की स्थिति में लोगों का उम्मेद बताने के तरीके

- आवश्यक बचाव उपकरण

5- अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना

अतः आपदा प्रबंधन में DDR के द्वारा क्षति को कम किया जा सकता है इसके लिए SDG, UNFCCC तथा सिंजाई डेमवर्क को स्वीकृत करने की जरूरत है।

17. Provide an account of the existing carbon trading mechanisms in India. Also, discuss the significance of an efficient carbon trading market in the country and state the challenges that currently exist. (250 words) 15

भारत में मौजूदा कार्बन व्यापार तंत्र का विवरण प्रस्तुत कीजिए। साथ ही, देश में एक कुशल कार्बन व्यापार बाजार के महत्व पर चर्चा कीजिए और वर्तमान समय में विद्यमान चुनौतियों का उल्लेख कीजिए।

कार्बन व्यापार तंत्र की व्यवस्था क्यौरी प्रोटोकॉल के तहत लाई गई थी ताकि देशों को उनके लिए निर्धारित कार्बन लक्ष्यों को प्राप्त करने में आसानी हो।

भारत जैसे विकासशील देशों के लिए क्लीन डेवलपमेंट स्कीम (CDs) प्रणाली के तहत कार्बन व्यापार तंत्र की व्यवस्था की गई थी। इसमें भारत अपने द्वारा निर्धारित लक्ष्यों से कम उत्सर्जन पर कार्बन क्रेडिट की श्रृंखला सृजित करता है जिसे विकसित देशों को बेच सकता है।

कुशल कार्बन व्यापार बाजार का महत्व

1 - कुशल कार्बन व्यापार बाजार कार्बन

ड्रेडिट का तीव्र व सुविधाजनक लेन
देन को संभव बनाता है जिससे
जलवायु परिवर्तन से निपटने में
सहायता ।

2- कार्बन ड्रेडिट के विक्रय से भारत को
बड़े मात्रा में वित्त की उच्च बिक्री
उद्योग जलवायु परिवर्तन से निपटने
के उपायों में ।

3- इस व्यवस्था से तबत भारत को
नवीन तकनीक भी प्राप्त होगी है ।

4- जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में भारत
की प्रगति धूमिल सुनिश्चित होगी

वर्तमान समय में कार्बन बाजार के समझ
चुनें लियें

1- देशों द्वारा उत्सर्जन मानकों को समुचित
पालन न करना ।

2- इस व्यवस्था के माध्यम से विकसित
देश जीव देशों के पर्यावरण को

हानि पहुँचा रहे हैं।

3. गरीब देशों द्वारा कार्बन डैडिट में
धन शक्ति के बालन में विकास कार्यों
को धीमा करना जिससे जनता का
कल्याण प्रभावित

4 - बाजार का समुचित विकास नहीं -
कई तकनीकी, संस्थागत व प्रचिनन
उद्वेगनाइयाँ।

जलवायु परिवर्तन वर्तमान में
सम्पूर्ण विश्व के समक्ष एक प्रमुख कतरा
है मतः सभी देशों को इसके साथ
मिलकर प्रयास करना चाहिए ताकि
भविष्य की पीढ़ियों के लिए बेहतर
भविष्य निर्मित हो सके।

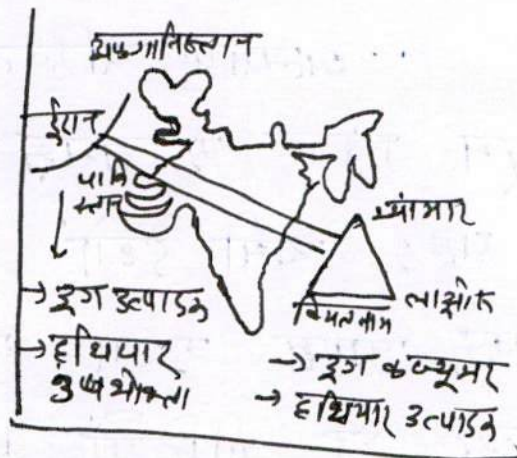
18. The menace of drug trafficking in India has been on a rise due to a mix of factors, both internal and external. Discuss. Also, state the challenges posed by drug trafficking to India's national security. (250 words) 15

भारत में ड्रग ट्रेफिकिंग का खतरा आंतरिक और बाह्य दोनों कारकों के समन्वय के कारण बढ़ रहा है। चर्चा कीजिए। साथ ही, भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के समक्ष ड्रग ट्रेफिकिंग से उत्पन्न चुनौतियों का उल्लेख कीजिए।

ड्रग ट्रेफिकिंग का तात्पर्य पर
अवैध रूप से शरीर भागा में द्रव्य का
आदान-प्रदान करने है।

ड्रग ट्रेफिकिंग से लिए उत्तरदायी बाह्य कारक

1. भारत की भौगोलिक
स्थिति गोलडन रिसेटिंग
प गोलडन ट्रायंगल के
मध्य → मतः ड्रग
ट्रेफिकिंग को बढ़ावा



2. बाह्य सीमाएँ - खुली व हिंडल
[नेपाल, बांग्लादेश आदि के साथ]

आंतरिक कारक

1- सीमावर्ती क्षेत्रों में कम विकास के
कारण गरीब जनता इस कार्य में

अधिक कुश्रैद्य ।

2- सर्वेध मापुवासियों की अहमधिक कंठमा
भारत → जिससे इग ट्रेफिकिंग से
बढ़ावा

3- सीमाओं के दोनों पार समान नृजातीय
वस्तुओं की उपस्थिति → ऐसे में बार्बाई
करना बढ़ेगा ।

4- देश के अन्तर् से नक्सली, शूर्वेतर
अपवाधियों द्वारा इसे बढ़ावा देना ।

दुरक्षा चुनौतियाँ - इग ट्रेफिकिंग से

1- सीमा पर सर्वेध गतिविधियों में इहृ
हो जाती है जिससे सीमाएं अधिक
कुश्रैद्य

2- इग ट्रेफिकिंग, संगठित अपराध-क
नार्दी टेरेर बैदी चुनौतियाँ उत्पन्न
करता है ।

3- इग तल्बरी से नक्सलवादियों व

अंगवर्धियों को धन की आपूर्ति जिससे
उनकी स्थिति अधिक सुदृढ़ ।

4 - ऐसे देश में वैश्यावृत्ति, मानव
व पशु तस्करी को बड़ा बाधा मिलता
है।

5 - देश में अपराधों में वृद्धि तथा
धुन धन शक्ति का ह्रास होगा ।

सरकार ने इस दिशा में
उपास करते हुए सीमाओं पर CIBMS
तथा ICP के द्वारा निगरानी व अपराधियों
पर कड़ी कार्रवाई के माध्यम से
इस समस्या को नियंत्रण का उपास
किया, किन्तु इसके लिए वैश्विक
सहयोग पर भी बल देना चाहिए ।

19. The Andaman and Nicobar islands' strategic significance in the Indian Ocean region (IOR) has been underplayed by India's policy of 'masterly inactivity and benign neglect'. Critically discuss. (250 words) 15

हिंद महासागर क्षेत्र (IOR) में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के रणनीतिक महत्व को भारत की 'कुशल अकर्मण्यता और सौम्य उपेक्षा' की नीति के तहत कम करके आंका गया है। समालोचनात्मक चर्चा कीजिए।

भारत हिन्द महासागर के शीर्ष पर स्थित है और 70% मार्ग के अनुसार तथा 90% मूल्य के अनुसार अपना व्यापार हिन्द महासागर से करता है तथा प्रमुख SLOCs की उपस्थिति ~~IOR~~ को अधिक रणनीतिक क्षेत्र बना देती है।

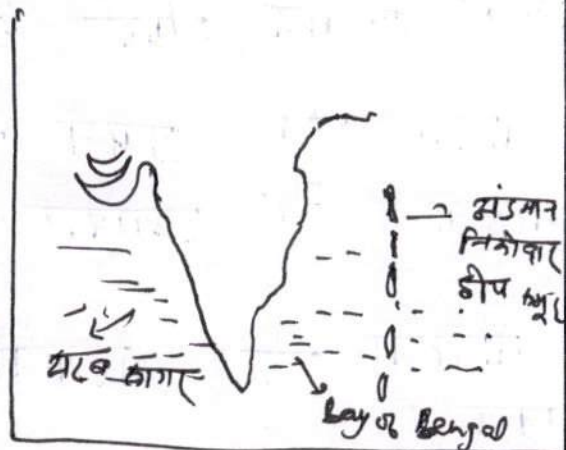
अंडमान निकोबार का महत्व -

1- भारत के EEZ क्षेत्र का विस्तार

2- प्रमुख समुद्री मार्गों पर यहाँ से प्रिगरासि

3- IOR में बेहतर उपस्थिति बनाए रखने में सहायक

4- आसियान देशों से निकटता



कुछ आलोचकों का तर्क है कि भारत ने 102 में अष्टमान के रणनीतिक महत्व के बावजूद उसे पर्याप्त ध्यान नहीं दिया है —

- 1 - अष्टमान में सभी विकास बहुत कम हैं।
- 2 - कनेक्टरविहीन, डा. पर्याप्त व्यवस्था है।

लेकिन सरकार ने अष्टमान के महत्व को समझते हुए इसके विकास के लिए प्रयास किए हैं जैसे —

- 1 - भारत की प्रथम थ्रिसेक्टर समूह अष्टमान में स्थापित की गई।
- 2 - नौसेना के अत्याधुनिक बेस का निर्माण किया।
- 3 - एयरपोर्ट, से-य रनवे आदि का निर्माण किया।
- 4 - हाल ही में अष्टमान में 46 कनेक्टरों को इतिहास किया गया।

चूँकि मध्यमान राजनीतिक रूप से
अल्पवर्गीय होते हुए भी पर्यावरणीय
हानि से अत्यधिक संवेदनशील हैं
अतः सरकार को पर्यावरण व सामाजिक
हानि से संतुलन बनाए रखते हुए
JCL में अपनी भूमिका को बढ़ाते हुए
मध्यमान मिश्रण नीति समूह पर ध्यान
देना चाहिए ।

20. India has recently commissioned the world's first large International Liquid-Mirror Telescope (ILMT). How will the newly commissioned telescope aid in India's astronomical observations and research? (250 words) 15

हाल ही में, भारत ने विश्व का पहला विशाल इंटरनेशनल लिक्विड-मिरर टेलीस्कोप (ILMT) स्थापित किया है। यह नवनिर्मित टेलीस्कोप खगोलीय पर्यवेक्षणों और अनुसंधान में भारत की किस प्रकार सहायता करेगा?

अंतरिक्ष अन्वेषण व खगोलीय पर्यवेक्षणों के लिए विभिन्न देश टेलीस्कोप को स्थापित करते हैं। NASA द्वारा स्थापित जेम्स वेब, हबल टेलीस्कोप आदि हैं।

भारत में आत्मनिर्भर भारत अभियान की भावना के अनुरूप विश्व की पहली इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप (ILMT) स्थापित की है।

→ इससे भारत की वैश्व स्तर पर तकनीकी प्रगति के क्षेत्र में बेहतर छवि बनेगी।

→ खगोलीय पर्यवेक्षण के लिए अब अन्य देशों पर निर्भर नहीं।

रहना होगा।

→ निरविवश मिरर होने के कारण
इसकी क्षमता अत्यधिक उच्च है
और सही ढंग पर प्रदान करने में
मदद करेगी।

→ इसकी कक्षा ने भारत में
अंतरिक्ष संबंधी अनुसंधानों में
तीव्रता ला सकता है।

